संसाधनों की बरबादी और पानी का संकट

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

हाल ही में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्पन्न विश्व जल सम्मेलन में विद्वानों ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर हमने संसाधनों की बरबादी पर रोक नहीं लगाई तो वह दिन दूर नहीं जब हमें भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे लोग जब किसी भी तरह के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो अंततः वह पानी जैसे जीवनदायी संसाधन की बरबादी में परिणत हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि विश्व में उत्पादित अनाजों का 50 प्रतिशत भाग बरबाद हो जाता है। स्टॉकहोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान का कहना है कि अगर हम खलिहानों, परिवहन, दुकानों, सुपर बाज़ारों, जलपान गृहों, होटलों और रसोई घरों में बरबाद होने वाले खाद्यान्न की मात्रा को जोड़ें तो पाएंगे कि यह हमारे कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधे के बराबर होगी। इस बरबादी के लिए सम्पन्न और मध्यम आय वर्ग के साथ-साथ विकासशील तथा विकसित सभी तरह के राष्ट्र किसी-न-किसी रूप में ज़िम्मेदार हैं। यही नहीं, पूरा विकासशील जगत अमेरिका का अनुकरण करने में लगा है जो संसाधनों की बरबादी का चरम प्रतीक है और इस अनुकरण को ही विकास की संज्ञा दी जा रही है।

अमेरिका की जीवन शैली में किस तरह संसाधनों की बरबादी होती है, इसे देखा जाना चाहिए। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वहां के नागरिक 30 प्रतिशत खाद्य सामग्री तो उपभोग के अंतिम चरण पर ही बरबाद करते हैं; उत्पादन, परिवहन, प्रसंस्करण आदि के दौरान होने वाली बरबादी इससे अलग है। अंतिम चरण पर बरबाद होने वाली सामग्री के उत्पादन, प्रसंस्करण आदि में कुल मिलाकर 400 खरब लीटर पानी प्रयुक्त होता है। इतना पानी 50 करोड़ लोगों की एक वर्ष की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

विकासशील राष्ट्रों में उपयोग के अंतिम चरण की अपेक्षा खाद्य सामग्री के उत्पादन, परिवहन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि के दौरान संसाधनों की बरबादी अधिक होती है। शीघ्र बरबाद होने वाली सब्ज़ियां, फल आदि त्वरित परिवहन, समुचित भण्डारण के लिए शीतगृहों आदि के अभाव में काफी मात्रा में बरबाद हो जाते हैं। फिर समय के साथ-साथ भारत जैसे शाकाहारी राष्ट्र में भी मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अन्न, फल, सब्ज़ियों की तुलना में मांस के उत्पादन में संसाधनों की अधिक खपत होती है। एक किलो गौमांस के उत्पादन के लिए 10 से 15 टन पानी की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि मांसाहार की दिशा में बढ़ने पर बड़ी मात्रा में पानी की बरबादी होगी। मांस के उपभोग के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, परंतु इसकी तुलना में कई गुना कम पानी की मांग करने वाले प्रोटीन के अन्य स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे दालें वगैरह।

केवल उपभोग के स्तर पर ही नहीं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भी हम संसाधनों की भारी बरबादी करते हैं। भारत का ही उदाहरण लें तो हमने उत्पादन वृद्धि के लिए बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है परंतु ये सिंचाई योजनाएं पानी की बरबादी का प्रतीक बन गई हैं। प्रति हेक्टेयर कृषि के लिए सिंचाई आयोग द्वारा मान्य

वर्ग पहेली 49 का हल

इ	ले	क्ट्रॉ	न		प्रा	थ	मि	क
ह			क्ष	र	ण			प
लौ	ह		त्र		घा	स	ले	ट
कि		त		ख	त			
क	शे	रु	क		क	ट	ह	ल
			श	ब		न		सि
स	र	ग	म		अ		छीं	का
चे			क	छा	र			तं
त	र	क	श		बी	ज	प	त्र

आवश्यक पानी की मात्रा की अपेक्षा इनमें औसतन 50 प्रतिशत अधिक पानी खर्च होता है। भूजल से सिंचाई की प्रक्रिया में सरकार द्वारा सिंचाई हेतु निशुल्क या सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के कारण दोहन किए जाने वाले पानी की लागत कम हो जाती है। अतः किसान पानी के उपयोग में किफायत के कोई प्रयास नहीं करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने विपुल उत्पादन देने वाले जिन बीजों का विकास किया है, उनसे भी सिंचाई की आवश्यकता बढ़ती है। इन सारे कारणों से कृषि में पानी की मांग में वृद्धि होती है। अगर असिंचित कृषि के लिए भी ऐसे ही विपुल उत्पादन वाले बीजों का विकास कर लिया जाता तो पानी के उपयोग और बरबादी को कम किया जा सकता था।

हमें संसाधनों और पानी की बरबादी को रोकने की दिशा में प्रयास करने ही होंगे। विश्व खाद्य संगठन का कथन है कि अगर हमने बरबादी को रोकने की दिशा में प्रयास नहीं किए, तो वह दिन दूर नहीं जब बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न और पानी उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान का कथन है कि लोगों की संसाधनों और पानी की फिज़ूलखर्ची की आदतों को बदलने के लिए हमें उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन देना होंगे। स्वीडन का उदाहरण देते हुए संस्थान का कथन है कि स्वीडन में पानी की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप पानी की खपत में 30 प्रतिशत कमी आई है। पानी के अभाव वाले देश कुवैत की सरकार उपभोक्ताओं को पानी निशुल्क उपलब्ध कराती है, जबकि स्वीडन, जहां पानी प्रचुरता में उपलब्ध है, में सरकार उसे कीमत के बदले उपलब्ध कराती है। परिणाम यह रहा है कि कुवैत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की औसत खपत 600 लीटर है जबकि स्वीडन में यह मात्र 150 लीटर अर्थात एक चौथाई ही है। भारत जैसे राष्ट्र में पानी की कीमत बढ़ाने के पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब आबादी को इसकी उपलब्धता बनी रहे, अन्यथा पानी गरीबों की पहुंच से परे हो जाएगा और इसके सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बंधी दुष्प्रभाव और भी अधिक गहन हो सकते हैं। परंतु किसी न किसी प्रकार से इस देश के सम्पन्न नागरिकों द्वारा की जाने वाली पानी की बरबादी को रोकना ही होगा। अगर हमने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो स्थिति कितनी भयावह होगी, इसकी कल्पना ही हमें सिहरा देती है। ***(स्रोत फीचर्स)***

अगले अंक में

स्रोत दिसम्बर 2008

अंक 239

- **रंगों से जीवन रक्षा**
- **जयपुर फुट के रचयिता डॉ. पी. के. सेठी**
- **गेरूआ रोग की कहानी का नया संस्करण**
- **सौर मण्डल से बाहर के ग्रह**
- **शास्त्रीय संगीत में कितने राग हैं?**